प्रेस विज्ञप्ति

12 मार्च, 2018

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व श्री आर. पी. एन. सिंह, प्रवक्ता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित बयान जारी किया:-

मोदी सरकार बनी किसान के लिए 'आत्महत्या का अभिशाप'
मुट्ठी-भर अमीरों के लिए दरियादिली- किसानों को दर्द बाँट रही भाजपा सरकार'
कांग्रेस व किसान लड़ेंगे कुरुक्षेत्र का 'न्याययुद्ध'

आज 50 हजार किसान मुंबई में मोदी और फड़नवीस सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 180 किलोमीटर पदयात्रा कर महाराष्ट्र विधान सभा के घेराव पर हैं। भाजपा सरकारों ने बैंकों के हज़ारों करोड़ लूटने वालों की किस्मत में देश छोड़कर भाग जाने की सौगात लिख दी और हजारों किसानों के भाग्य में आत्महत्या का अभिशाप। मोदी सरकार के चार सालों में देश के हर प्रान्त में करोड़ों किसान आंदोलित हैं। कहीं आजीविका के लिए विवश होकर आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं सिर मुंडवाकर प्रदर्शन, तो कहीं नरकंकालों तथा स्वयं का मल-मूत्र ग्रहण कर व्यथा की व्याख्या। भाजपा सरकारें उन्हें बदले में दे रही हैं सीने पर गोलियां और शरीर पर लाठियां - चाहे मंदसौर व रायसेन (मध्यप्रदेश) हों या फिर दाहोद (गुजरात), सीकर (राजस्थान), शाहबाद (हरियाणा) हों।

भाजपा युवा मोर्चा की प्रमुख तथा सांसद, सुश्री पूनम महाजन महाराष्ट्र के इन किसानों को नक्सलवादी बताती हैं तो मुख्यमंत्री, श्री देवेंद्र फड़नवीस उन्हें आदिवासी कहकर सिरे से खारिज कर देते हैं। भाजपा की किसान विरोधी मानसिकता का सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि देश के कृषिमंत्री, श्री राधामोहन सिंह ने नपुंसकता व प्रेम प्रसंगों को किसान की आत्महत्या का कारण बताया था (24 जुलाई, 2015)। भाजपा के मंत्री व पूर्व किसान मोर्चा प्रमुख, श्री ओमप्रकाश धनकड़ ने तो किसानों को कायर व अपराधी का दर्जा दे डाला (29 अप्रैल, 2015)। अकोला, महाराष्ट्र के भाजपा सांसद, संजय धोत्रे ने तो विदर्भ के किसानों की आत्महत्या पर कहा कि किसानों को मरने दिया जाए (29 दिसंबर, 2014)। भाजपा के महाराष्ट्र प्रमुख, राव साहेब दानवे ने तो सभी हदें पार करते हुए तूअर दाल पैदा करने वाले किसानों को सार्वजनिक तौर से गाली दे डाली (12 मई, 2017)। यह भाजपा की किसान विरोधी असंवेदनशील मानसिकता को दिखाता है।

1. आत्महत्या की खेती व कर्जमाफी का धोखा:-

राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि मोदी सरकार के गठन के बाद किसानों की आत्महत्या 41.7 प्रतिशत बढ़ गई है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक किसान आत्महत्या हुई। अकेले 1 जनवरी- 31 अक्टूबर, 2017 तक 2,414 किसान आत्महत्या का आंकड़ा महाराष्ट्र के किसान की कहानी बताता है।

श्री नरेंद्र मोदी व श्री जेटली ने तो किसान कर्जमाफी से सरेआम केंद्र सरकार का पल्ला झाड़ लिया। महाराष्ट्र सरकार ने जून 2017 में 89 लाख किसानों से कर्जमाफी का वादा किया। एक षड़यंत्र के तहत किसानों से आधार लिंक्ड ऑनलाईन आवेदन मंगाने के नाम पर लगभग 30 लाख किसानों को इस कर्जमाफी योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया। महाराष्ट्र में आदिवासी किसानों को वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टे न दे सरकार उनकी खड़ी फसलों को रौंद देती है। महाराष्ट्र में 3,64,358 आदिवासी पट्टों के आवेदन में से भाजपा सरकार ने 2,31,856 पट्टे निरस्त कर दिये गये। उल्टा भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने नए नियम जारी कर आदिवासियों की जमीन को (उनकी बगैर राय के) सरकार की मनमर्जी से इस्तेमाल का फरमान जारी कर दिया। यहां तक कि महाराष्ट्र में मोटे अनाज, दालों व तिलहन का रकबा भी क्रमशः 42%, 6% व 60% कम हो गया है। 5 जनवरी, 2018 के सर्वेक्षण के मुताबिक इस साल महाराष्ट्र में रबी फसल का रकबा 31% कम हुआ है। यह अभूतपूर्व कृषि संकट को दर्शाता है।

2. किसानों की 'स्वामीनाथन कमेटी' खारिज - मोदी जी की 'जुमलानाथन' कमेटी शुरु

श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा ने सन 2014 लोकसभा चुनाव व अपने घोषणापत्र (पृष्ठ 44) में वायदा किया कि वो किसान को 'लागत + 50%' का समर्थन मूल्य (MSP) देंगे। मगर मोदी सरकार ने 20 फरवरी, 2015 को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे कहा कि किसान को 'लागत + 50% मुनाफा' कभी नहीं दिया जा सकता।

वित्तमंत्री, श्री अरुण जेटली ने बजट भाषण 2018-19 (1 फरवरी, 2018) को संसद में सरेआम झूठ बोला कि मोदी सरकार पहले से ही 'लागत + 50% मुनाफा' दे रही है। अगर हम 'कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइस' 2018-19 रबी मार्केटिंग सीजन की रिपोर्ट देखें, तो कहीं भी 'लागत + 50% मुनाफा' नहीं दिया जा रहा।

Projected Cost of Production of Mandated Crops during Rabi Marketing Season, 2018-19

Crop	Cost of production (Rs. per Qtl.)	Cost+50% (Rs/Qtl.)	M S P	Difference of MSP & Cost+50%
Wheat	1,256	1884.00	1,735	149.00
Barley	1,190	1785.00	1,410	375.00
Gram	3,526	5289.00	4,400	889.00
Lentil	3,727	5590.50	4,250	1340.50
Rapeseed & Mustard	3,086	4629.00	4,000	629.00
Sunflower	3,979	5968.50	4,100	1868.50

इतना ही नहीं, 'कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइस' खरीफ मार्केटिंग सीजन 2017-18 के मुताबिक भी किसी भी फसल में 'लागत + 50%' मुनाफा नहीं दिया गया है। कृपया संलग्न टेबल A1 देखें। मोदी सरकार देश को यह भी नहीं बताती कि अलग-अलग राज्यों में पैदावार की लागत अलग-अलग आती है। जो लागत खुद मोदी सरकार ने निकाली है, राज्यवार देखने पर यह साफ साबित होता है कि 'लागत+50% मुनाफा' देना तो दूर की बात है, अनेकों राज्यों में किसान की लागत मूल्य से 24% से 32% तक कम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया गया है। कृपया संलग्न टेबल A1 देखें।

3. खेती उत्पादों का निर्यात गिरा, आयात बढ़ा - किसान को चूना, दलालों को लाभ

मोदी सरकार के 4 साल में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट लगातार घटा और विदेशों से एग्रीकल्चर इंपोर्ट लगातार बढ़ा। यानि किसान की फसल का निर्यात तो कम हो गया, तो कीमतें भी कम मिलीं। इसके विपरीत विदेश से कृषि उत्पादों का आयात बढ़ा जिससे एक बार फिर किसान की उपज की कीमतें कम हो गईं।

Value in USD Billion

Year	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Export	43.23	39.06	32.79	33.87
Import	15.03	20.62	22.06	25.09

हद तो यह है कि मोदी सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में दाल और गेहूं के बड़े-बड़े इंपोर्टर व दलालों को फायदा पहुंचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी 25% से 0% कर सस्ता अनाज विदेशों से मंगाया। 'कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइस' की रिपोर्ट बताती है कि आजाद भारत का सबसे अधिक आयात साल 2016-17 में हुआ जब मोदी सरकार ने 57.50 लाख टन गेहूं व 60.60 लाख टन दालें विदेश से आयात कर डालीं। यह इसके बावजूद किया गया जब 2016-17 में गेहूं का उत्पादन 983 लाख टन व दालों का उत्पादन 229 लाख टन था। क्या यह बिचौलियों को फायदा पहुंचाने की सोची समझी साजिश नहीं थी? साफ है कि मोदी सरकार किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाती है पर फायदा बिचौलियों को पहुंचाती है।